भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2575
दिनांक 13/12/2000 को उत्तर के लिए

राजभाषा का कार्यान्वयन

2575. श्री जनेश्वर मिश्रः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन में कोताही की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकतर विभागों में सारी फाईलें अंग्रेजी में ही तैयार की जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन विभागों का ब्यौरा क्या है जिनमें राजभाषा में 50 प्रतिशत से भी कम काम होता है?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (आई0 डी0 स्वामी)

(क): जी, नहीं ।

(ख): फाइलों पर नियमानुसार टिप्पणी हिंदी या अंग्रेजी में की जा सकती है । कार्मिक अपनी स्वेच्छा से किसी भी भाषा में टिप्पण और प्रारूपण कर सकता है । तदनुसार फाइलें हिंदी में भी तैयार की जाती हैं ।

(ग): उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता । तथापि संसद के 1967 के संकल्प के अनुसरण में एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है । अंतिम रिपोर्ट इस सदन में 8.12.1999 को रखी गयी थी ।

****

GOVERNMENT OF INDIA
(MINISTRY OF HOME AFFAIRS)

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2575
TO BE ANSWERED ON 13.12.2000

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

2575. SHRI JANESHWAR MISHRA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been a negligence in the implementation of official language in different Government offices;

(b) whether it is also a fact that all the files are prepared in English only in most of the departments; and

(c) if so, the details of the departments where less than 50 per cent work is done in official language?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(I.D. SWAMI)

(a): No, Sir.

(b): As per rules, noting on the files can be done either in Hindi or in English. An employee can do noting and drafting in any language according to his own will. Accordingly, files are prepared in Hindi also.

(c): In view of the above, question does not arise. However, in pursuance of the Parliamentary resolution of 1967, an Annual Assessment Report is placed on the table of both the houses. Last report was placed in the House on 8.12.1999.

******